(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Accident Prone Zone in Andhra Pradesh

420. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the most accident prone zone in Andhra Pradesh in the Aluru Tadepalligudum segment of the National Highways;

(b) whether any monitoring has been done of this accident prone sector; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATARAMAN): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

गुजरात सरकार की वस्त्र उत्पादन संबंधी परियोजनाएं

421. **श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई वस्त्र उत्पादन संबंधी परियोजनाएं अब भी केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) राज्य को परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब के कारण कितना वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर०एल० जालप्पा): (क) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई वस्त्र उत्पादन संबंधी कोई परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रायगढ़ जिला डाकघर में अंतिम भुगतान हेतु लंबित पड़े मामलों की संख्या

422. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रायगढ़ जिला डाकघर में नवम्बर, 1995 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अंतिम भुगतान के लिए कितने मामले लंबित पड़े थे;

(ख) कितने मामले छह माह से अधिक समय से लंबित पड़े हैं;

(ग) इन मामलों में तत्काल भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) विभाग द्वारा जमाकर्ताओं को समय पर पूरी राशि का भुगतान करने में क्या कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) महोदय, नवम्बर, 1995 तक रायगढ़ जिला डाकघर में बचत योजनाओं के अंतर्गत केवल 600 मामले अंतिम भुगतान के लिए लंबित है।

इन महीने से अधिक अवधि का कोई भी मामला अंतिम भुगतान के लिए लंबित नहीं है।

(ग) इन मामलों में भुगतान करने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई हैं।

(घ) विगत समय में डाकघर के कार्य में वृद्धि हुई है परन्तु जो अतिरिक्त कार्य बढ़ा है उसके अनुपात में स्टाफ उपलब्ध नहीं है। अंतिम भुगतान के लंबित मामले कर्मचारियों को मानदेय देकर निपटाए जा रहे हैं।

जल का उपयोग

423. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में औसतन वार्षिक, 1,170 एम०एम० वर्षा के माध्यम से जल की उपलब्धि होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में इस जल की बहुत कम मात्रा का ही उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें से सिंचाई, उद्योगों और पीने के लिए कितनी मात्रा का उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) सरकार शेष जल के उपयोग के लिए क्या योजना आरंभ करने का विचार रखती है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्रा): (क) जी हां

(ख) और (ग) वाष्पीकरण और निष्क्रिय (उत्सर्जन) जैसी हानियों तथा नदी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए नदी में कुछ जल को बहने देने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है। फिर भी, वर्षा जल की सीमित मात्रा का संचय करने के लिए नदी प्रणालियों पर बड़े, और छोटे बांधों तथा जलाशयों, भंडारणों का निर्माण किया जा सकता है। देश में 1142 बिलियन घन मीटर कुल उपयोज्य जल में से 536 बिलियन घन मीटर उपयोज्य जल को अप्रयुक्त छोड़ते हुए जल (सतही और भू) का वर्तमान (1994) उपयोग लगभग 606 बिलियन घन मीटर अर्थात् 53 प्रतिशत है।

(घ) विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल का वर्तमान (1994) उपयोग निम्न प्रकार है:—

प्रयोजन	उपयोग (बिलियन क्यूबिक मीटर में)
सिंचाई	501.00
पेयजल	30.40
ऊर्जा	20.20
उद्योग	20.00
अन्य	34.00
कुल	605.60

अर्थात् -606.

(ङ) पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए वर्षा जल का उपयोग करने हेतु नदियों पर भंडारण बनाने पर जोर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप देश की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता इस समय लगभग 193.2 बिलियन घन मीटर है। 77 बिलियन मीटर अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए बांध निर्माण के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त लगभग 130 बिलियन घन मीटर भंडारण, वृहद और मध्यम योजनाओं के जरिए बढ़ाए जाने की संभावना है, जो विचाराधीन है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधनों के विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना पर अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ नदियों को आपस में जोड़कर अधिशेष जल को कमी वाले बेसिनों में अन्तरित करने तथा संभावित स्थलों पर जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना है। अनुमान है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत अन्तरबेसिन अन्तरणों के जरिए उपयोग के लिए 220 बिलियन घन मीटर जल उपलब्ध होगा।

Modernisation of Textile Industry

424. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any new National Scheme for the modernisation of textile industry in the country.

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Declaration of River Waters as National Asset

425. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to declare river waters as a National asset so as to regulate their utilisation by the Central Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the principles evolved for division of the river waters among upper riparian and lower riparian States?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Generally principle of "equitable appointment" is followed. Draft national policy guidelines for water allocation amongst States were circulated in the third meeting of National Water Resources Council held on 6-2-1996.

भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी नागरिकों को सुविधाएं दिया जाना

426. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस.आर. सुरजेवाला:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए और अन्य सुविधाएं प्राप्त